COHERENCE – The Multidisciplinary Research Journal
Volume No: 16, Issue No: 2, Year: 2025 (July-December)
PP: 31-37
ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

बिहार में विश्व बैंक समर्थित महिला सशक्तीकरण एवं स्वयं सहायता समूह आधारित कार्यक्रमों का प्रभाव मूल्यांकन

मितु कुमारी

विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग,

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

सारांश

बिहार में महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया को केवल सामाजिक कल्याण के रूप में नहीं, बल्कि वित्तीय समावेशन, आजीविका-वृद्धि, सामुदायिक नेतृत्व, ऋण-सुलभता और ग्रामीण गरीबी-न्यूनीकरण की संयुक्त आर्थिक रणनीति के रूप में समझना आवश्यक है। इसी संदर्भ में विश्व बैंक समर्थित बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिसे जीविका के नाम से जाना जाता है, बिहार की ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों और क्लस्टर स्तरीय संघों के माध्यम से संगठित करने वाला एक बड़ा संस्थागत हस्तक्षेप रहा है। प्रस्तुत शोध-पत्र द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है और विश्व बैंक, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, जीविका की वार्षिक एवं प्रगति रिपोर्टों तथा उपलब्ध प्रभाव-मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर महिला सशक्तीकरण के आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जीविका ने बिहार में महिलाओं की वित्तीय पहुँच, बैंक-ऋण उपयोग, समूह आधारित बचत, सामाजिक सुरक्षा कवरेज, सामुदायिक भागीदारी और निर्णय-क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। तथापि, कार्यक्रम के समक्ष ऋण के उत्पादक उपयोग, क्षेत्रीय असमानता, आय-सृजन की स्थिरता, बाजार-संपर्क, कौशल-विस्तार और समूहों की दीर्घकालिक वित्तीय स्वायत्तता जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

मुख्य शब्द: जीविका, स्वयं सहायता समूह, महिला सशक्तीकरण, विश्व बैंक, बिहार, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण आजीविका

1. भूमिका

बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से कृषि-निर्भर, निम्न आय-स्तर वाली और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से प्रभावित रही है। ऐसी परिस्थिति में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सीमित होने के कारण घरेलू आय, बचत व्यवहार, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य-व्यय और पोषण-सुरक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। स्वयं सहायता समूह आधारित विकास मॉडल इसी समस्या के समाधान के रूप में उभरा, क्योंकि यह गरीब ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर बचत, आंतरिक ऋण, बैंक-लिंकिंग, सामुदायिक नेतृत्व और आजीविका-विस्तार से जोड़ता है। बिहार में विश्व बैंक समर्थित बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, अर्थात् जीविका, इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप है। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के अनुसार, यह परियोजना ग्रामीण गरीबों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से संचालित की गई है [1].

विश्व बैंक ने जीविका को भारत का सबसे बड़ा राज्य-स्तरीय कार्यक्रम बताया है, जो विशेष रूप से गरीब ग्रामीण परिवारों की महिलाओं के साथ कार्य करता है। 2008 से 2020 के बीच यह कार्यक्रम 12 million से अधिक ग्रामीण महिलाओं और 1.03 million स्वयं सहायता समूहों तक पहुँचा [2]. यह विस्तार केवल संख्या की दृष्टि से नहीं, बल्कि ग्रामीण सामाजिक संरचना में महिलाओं की सामूहिक उपस्थिति, वित्तीय पहचान और निर्णयात्मक भागीदारी की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। जीविका मॉडल ने

© Copyright @ Authors

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

महिलाओं को बैंकिंग व्यवस्था, बाजार, आजीविका प्रशिक्षण, स्वास्थ्य-व्यवहार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़कर विकास को बहुआयामी रूप दिया है।

इस शोध-पत्र का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि विश्व बैंक समर्थित जीविका जैसे स्वयं सहायता समूह आधारित कार्यक्रमों ने बिहार में महिला सशक्तीकरण को किस सीमा तक प्रभावित किया है। अध्ययन मुख्यतः तीन प्रश्नों पर केंद्रित है: पहला, क्या जीविका ने महिलाओं की वित्तीय पहुँच और ऋण-सुलभता में विस्तार किया है? दूसरा, क्या स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं के सामाजिक और निर्णयात्मक सशक्तीकरण को मजबूत किया है? तीसरा, कार्यक्रम के प्रभावों के बावजूद कौन-सी संरचनात्मक सीमाएँ बनी हुई हैं?

2. अध्ययन की पद्धति

यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। इसके लिए विश्व बैंक की परियोजना-रिपोर्टों, जीविका की वार्षिक रिपोर्टों, वित्तीय वर्ष 2024–25 के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट दस्तावेज, 2025 की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, तथा जीविका पर प्रकाशित प्रभाव-मूल्यांकन अध्ययनों का उपयोग किया गया है। विश्लेषण में वर्णनात्मक सांख्यिकी, प्रतिशत परिवर्तन, औसत आकार, प्रति समूह ऋण-प्रवाह, प्रति उद्यमी स्वीकृत ऋण और संस्थागत विस्तार दर जैसी गणनाओं का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन में उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों को तीन स्तरों पर व्यवस्थित किया गया है: संस्थागत विस्तार, वित्तीय समावेशन और सशक्तीकरण प्रभाव। संस्थागत विस्तार में स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों, क्लस्टर स्तरीय संघों और सदस्य परिवारों को लिया गया है। वित्तीय समावेशन में बैंक खाते, बैंक-ऋण लिंकिंग, कुल ऋण-प्रवाह, बीमा कवरेज और महिला उद्यम वित्त को शामिल किया गया है। सशक्तीकरण प्रभाव में गतिशीलता, निर्णय-क्षमता, सामुदायिक भागीदारी, ऋण-पोर्टफोलियो में परिवर्तन और आजीविका संबंधी परिणामों को देखा गया है।

3. जीविका कार्यक्रम की संरचना और विस्तार

जीविका का संस्थागत ढाँचा तीन प्रमुख स्तरों पर निर्मित है: स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तरीय संघ। स्वयं सहायता समूह 10–15 या 15–20 महिलाओं का आधारभूत बचत-ऋण समूह होता है। ग्राम संगठन कई स्वयं सहायता समूहों को जोड़ता है, जबकि क्लस्टर स्तरीय संघ बड़े क्षेत्रीय स्तर पर सामुदायिक संस्थाओं को वित्तीय, सामाजिक और प्रशासनिक समर्थन देता है। विश्व बैंक के सूक्ष्म आँकड़ा-संग्रह के अनुसार जीविका स्वयं सहायता समूहों को बचत और ऋण आधारित महिला समूहों के रूप में विकसित करता है, जिनका उद्देश्य आजीविका और घरेलू आय में सुधार करना है [3].

वित्तीय वर्ष 2024–25 के जीविका दस्तावेज में बताया गया कि बिहार में 10.45 lakh स्वयं सहायता समूह बन चुके थे और 1.30 crore महिलाएँ इनसे जुड़ी थीं [4]. सितंबर 2025 तक यह विस्तार 11.40 lakh स्वयं सहायता समूहों, 73,515 ग्राम संगठनों और 1,684 क्लस्टर स्तरीय संघों तक पहुँच गया। इसी रिपोर्ट के अनुसार, कार्यक्रम की संचयी पहुँच 1.40 crore परिवारों से अधिक हो चुकी थी [5]. इससे स्पष्ट है कि जीविका केवल परियोजना नहीं, बल्कि बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला-आधारित सामुदायिक संस्थागत ढाँचे के रूप में स्थापित हो चुकी है।

© Copyright @ Authors

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

तालिका 1: जीविका के संस्थागत विस्तार के प्रमुख संकेतक

संकेतक	2020 के आसपास	2024–25	सितंबर 2025
महिला सदस्य / परिवार	12 million से अधिक	1.30 crore महिलाएँ	1.40 crore परिवार से अधिक
स्वयं सहायता समूह	1.03 million	10.45 lakh	11.40 lakh
ग्राम संगठन	—	—	73,515
क्लस्टर स्तरीय संघ	—	—	1,684
औसत सदस्य/SHG	लगभग 11.65	लगभग 12.44	लगभग 12.28

2020 में 1.03 million स्वयं सहायता समूहों से 2025 में 11.40 lakh समूहों तक वृद्धि लगभग 10.68% है। इसी अवधि में महिला/परिवार पहुँच 12 million से बढ़कर 14 million से अधिक हुई, अर्थात् लगभग 16.67% की वृद्धि दिखाई देती है। यह वृद्धि बताती है कि कार्यक्रम का विस्तार केवल समूहों की संख्या में नहीं, बल्कि प्रति समूह सदस्यता और ग्रामीण परिवार कवरेज में भी हुआ है।

4. वित्तीय समावेशन पर प्रभाव

जीविका का सबसे ठोस आर्थिक प्रभाव वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में दिखाई देता है। सितंबर 2025 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, 10,49,411 स्वयं सहायता समूह बचत खाते खोले जा चुके थे। 25,25,434 समूहों ने बैंक ऋण के अनेक दौर प्राप्त किए और कुल ऋण-प्रवाह ₹59,156 crore तक पहुँचा [5]. यह आँकड़ा दर्शाता है कि जीविका ने गरीब ग्रामीण महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर जोड़ा।

तालिका 2: जीविका के वित्तीय समावेशन संकेतक, सितंबर 2025

संकेतक	मूल्य
SHG बचत खाते	10,49,411
बैंक ऋण लिंकिंग के संचयी दौर	25,25,434
कुल ऋण-प्रवाह	₹59,156 crore
महिला उद्यमियों को स्वीकृत राशि	₹57.60 crore
लाभान्वित महिला उद्यमी	14,328
PMJJBY कवरेज	80.52 lakh SHG सदस्य
PMSBY कवरेज	91.12 lakh SHG सदस्य
तिमाही CSP लेन-देन	₹2,619.31 crore

कुल ऋण-प्रवाह ₹59,156 crore को 25,25,434 बैंक-लिंकिंग दौरों से विभाजित करने पर प्रति ऋण-लिंकिंग औसत राशि लगभग ₹2.34 lakh आती है। इसी प्रकार, कुल ऋण-प्रवाह को 10,49,411 SHG बचत खातों से विभाजित करने पर प्रति SHG बचत खाते औसत ऋण-प्रवाह लगभग ₹5.64 lakh

© Copyright @ Authors

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

बैठता है। महिला उद्यम वित्त के अंतर्गत ₹57.60 crore की स्वीकृति 14,328 महिलाओं को दी गई, जिससे प्रति महिला उद्यमी औसत स्वीकृत राशि लगभग ₹40,200 है।

ये आँकड़े यह संकेत देते हैं कि जीविका ने ग्रामीण महिलाओं को केवल सूक्ष्म बचत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें बैंक ऋण, उद्यम वित्त और बीमा से भी जोड़ा है। वित्तीय समावेशन का यह मॉडल ग्रामीण गरीबी-न्यूनीकरण में इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह साहूकारी और उच्च ब्याज वाले अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता को कम करता है।

दत्ता के प्रभाव-मूल्यांकन अध्ययन में भी यह पाया गया कि जीविका ने लाभार्थी परिवारों के ऋण-पोर्टफोलियो को बदला, उच्च लागत वाले ऋण-भार को कम किया और महिलाओं के सशक्तीकरण के विभिन्न आयामों में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया [6]. इस प्रकार, द्वितीयक सांख्यिकीय प्रमाण और प्रभाव-मूल्यांकन दोनों वित्तीय समावेशन के पक्ष में सुसंगत निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं।

5. महिला सशक्तीकरण पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

महिला सशक्तीकरण को केवल आय-वृद्धि के आधार पर नहीं मापा जा सकता। इसके लिए गतिशीलता, सामुदायिक भागीदारी, निर्णय-क्षमता, संस्थागत पहचान, ऋण-प्रबंधन, बाजार-संपर्क और सामाजिक आत्मविश्वास को भी समझना आवश्यक है। विश्व बैंक की प्रभाव-नोट के अनुसार, जीविका ने महिलाओं की गतिशीलता, निर्णय-निर्माण में भागीदारी और सामुदायिक सामूहिक कार्य में संलग्नता को बढ़ाया [7].

आर्थिक दृष्टि से स्वयं सहायता समूह महिलाओं को बचत अनुशासन, ऋण उपयोग और सामूहिक गारंटी की क्षमता प्रदान करते हैं। सामाजिक दृष्टि से वे महिलाओं को सार्वजनिक बैठकों, पंचायत-स्तरीय संवाद, ग्राम संगठन, पोषण अभियान, स्वच्छता अभियान और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ते हैं। यही कारण है कि जीविका को केवल माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम नहीं माना जा सकता; यह ग्रामीण महिला नेतृत्व का संस्थागत मंच भी है।

विश्व बैंक के अनुसार, जीविका के माध्यम से 2014–2020 के बीच 2.08 million ग्रामीण महिलाओं को सार्वजनिक बीमा योजनाओं में नामांकित किया गया और 285,000 महिला लघु कृषकों को कमोडिटी आधारित किसान उत्पादक संगठनों से जोड़ा गया [2]. इससे स्पष्ट होता है कि कार्यक्रम ने कृषि, गैर-कृषि उद्यम, बीमा और बाजार-संपर्क को महिला सशक्तीकरण के साथ जोड़ा।

तालिका 3: महिला सशक्तीकरण के प्रभाव-क्षेत्र

प्रभाव-क्षेत्र	प्रमुख परिवर्तन	आर्थिक अर्थ
वित्तीय पहुँच	बैंक खाता, ऋण लिंकिंग, बीमा	औपचारिक वित्त पर निर्भरता
सामाजिक पूँजी	SHG, VO, CLF में भागीदारी	सामूहिक सौदेबाजी क्षमता
निर्णय-क्षमता	घरेलू एवं सामुदायिक निर्णयों में भूमिका	संसाधन आवंटन में महिला भागीदारी
आजीविका	कृषि, उद्यम, उत्पादक समूह	आय-स्रोतों का विविधीकरण
सामाजिक सुरक्षा	PMJJBY, PMSBY कवरेज	जोखिम-प्रबंधन क्षमता
नेतृत्व	सामुदायिक कैडर, बैंक सखी, CSP	ग्रामीण सेवा-प्रदाय में महिला भूमिका

© Copyright @ Authors

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

6. प्रभाव-मूल्यांकन हेतु संकेतक-आधारित विश्लेषण

इस अध्ययन में उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर एक सरल संकेतक-आधारित मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए तीन सूचक बनाए गए हैं: संस्थागत सुदृढ़ता सूचक, वित्तीय समावेशन सूचक और आजीविका-सशक्तीकरण सूचक। प्रत्येक सूचक को उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर 0 से 100 के पैमाने पर व्याख्यात्मक रूप से रखा गया है।

तालिका 4: जीविका का संकेतक-आधारित प्रभाव मूल्यांकन

सूचक	प्रयुक्त संकेतक	मूल्यांकन
संस्थागत सुदृढ़ता	11.40 lakh SHG, 73,515 VO, 1,684 CLF	उच्च
वित्तीय समावेशन	₹59,156 crore ऋण-प्रवाह, 10.49 lakh खाते	बहुत उच्च
सामाजिक सुरक्षा	80.52 lakh PMJJBY, 91.12 lakh PMSBY	उच्च
उद्यम वित्त	₹57.60 crore, 14,328 महिला उद्यमी	मध्यम
बाजार-संपर्क	उत्पादक समूह, ग्रामीण रिटेल, शिल्पग्राम	मध्यम
दीर्घकालिक आय-स्थिरता	उपलब्ध प्रमाण मिश्रित	मध्यम

इस तालिका से स्पष्ट है कि जीविका का सबसे मजबूत प्रभाव संस्थागत विस्तार और वित्तीय समावेशन में है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज भी पर्याप्त है। परंतु उद्यम वित्त, बाजार-संपर्क और स्थिर आय-सृजन के क्षेत्र में अभी और विस्तार की आवश्यकता है। दत्ता के अध्ययन में भी यह बताया गया कि ऋण-पोर्टफोलियो और महिला सशक्तीकरण पर मजबूत प्रभाव दिखता है, परंतु आजीविका विकल्पों, विशेषतः कृषि में बहुत बड़ा परिवर्तन स्पष्ट नहीं था [6].

7. उपलब्धियाँ

जीविका की पहली उपलब्धि यह है कि इसने बिहार में गरीब ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक पहचान दी। सामाजिक रूप से वंचित महिलाएँ, जो पहले बैंक, पंचायत, बाजार और सरकारी योजनाओं से दूर थीं, अब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन संस्थाओं से जुड़ सकीं। दूसरी उपलब्धि वित्तीय समावेशन है। ₹59,156 crore का संचयी ऋण-प्रवाह किसी भी राज्य-स्तरीय महिला समूह कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है [5].

तीसरी उपलब्धि सामाजिक पूँजी का निर्माण है। ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तरीय संघ महिलाओं के सामूहिक नेतृत्व को स्थायित्व देते हैं। चौथी उपलब्धि ग्रामीण सेवा-प्रदाय में महिलाओं की भूमिका है। बैंक सखी, सामुदायिक कैडर, किसान उत्पादक समूह और महिला उद्यमी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई भूमिका निभा रही हैं। पाँचवीं उपलब्धि यह है कि कार्यक्रम ने स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता को आजीविका से जोड़ा। विश्व बैंक के माइक्रोडाटा विवरण के अनुसार, जीविका के महिला समूहों को पोषण-परिणाम सुधारने के लिए बहु-क्षेत्रीय अभिसरण पहल में भी उपयोग किया गया [3].

8. सीमाएँ और चुनौतियाँ

जीविका के व्यापक विस्तार के बावजूद कुछ महत्त्वपूर्ण सीमाएँ सामने आती हैं। पहली सीमा यह है कि ऋण की उपलब्धता हमेशा उत्पादक आय में परिवर्तित नहीं होती। कई बार ऋण का उपयोग उपभोग, सामाजिक दायित्व, स्वास्थ्य-व्यय या पुराने ऋण चुकाने में हो जाता है। यह गरीब परिवारों की वास्तविक आवश्यकता भी हो सकती है, परंतु इससे उद्यम-आधारित आय-वृद्धि सीमित रह जाती है।

© Copyright @ Authors

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

दूसरी चुनौती क्षेत्रीय असमानता है। बिहार के सभी जिलों और प्रखंडों में समूहों की परिपक्वता समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह वित्तीय रूप से सक्रिय हैं, जबकि कुछ स्थानों पर समूह बैठक, लेखांकन, डिजिटल रिकॉर्ड और बैंक समन्वय कमजोर हो सकता है। तीसरी चुनौती बाजार-संपर्क है। महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को स्थायी बाजार, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और ई-कॉमर्स से जोड़ना अभी भी एक बड़ा कार्य है।

चौथी चुनौती समूहों की ऋण-अवशोषण क्षमता है। यदि ऋण बढ़ता है पर आय-स्रोत स्थिर नहीं होते, तो समूहों पर पुनर्भुगतान दबाव बढ़ सकता है। पाँचवीं चुनौती महिला श्रम के अदृश्य बोझ से संबंधित है। SHG बैठकों, उद्यम, कृषि कार्य, घरेलू कार्य और देखभाल-कार्य के बीच महिलाओं का समय-भार बढ़ सकता है। इसलिए महिला सशक्तीकरण का वास्तविक अर्थ केवल ऋण-सुलभता नहीं, बल्कि समय, आय, निर्णय और सामाजिक सम्मान में संतुलित सुधार होना चाहिए।

9. नीति-सुझाव

पहला, जीविका के अंतर्गत ऋण-लिंकिंग को उद्यम-मार्गदर्शन, बाजार-संपर्क और वित्तीय परामर्श से जोड़ना चाहिए। केवल ऋण वितरण से स्थायी आय-सृजन सुनिश्चित नहीं होता। दूसरा, प्रत्येक क्लस्टर स्तरीय संघ में उद्यम परामर्श केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, जहाँ व्यवसाय योजना, लागत-लाभ विश्लेषण, डिजिटल भुगतान, GST जागरूकता, पैकेजिंग और बाजार-विस्तार पर प्रशिक्षण दिया जाए।

तीसरा, महिला उद्यमियों के लिए छोटी राशि के साथ-साथ वृद्धि-उन्मुख ऋण की अलग श्रेणी बनाई जानी चाहिए। सितंबर 2025 के आँकड़ों के अनुसार प्रति महिला उद्यमी औसत स्वीकृत राशि लगभग ₹40,200 है, जो सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए उपयोगी है, परंतु विस्तार-उद्यम के लिए अपर्याप्त हो सकती है [5]. चौथा, कृषि आधारित महिला उत्पादक समूहों को मूल्य-श्रृंखला, भंडारण, प्रसंस्करण और डिजिटल विपणन से जोड़ा जाना चाहिए। पाँचवाँ, प्रभाव-मूल्यांकन की नियमित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिसमें केवल SHG संख्या और ऋण-प्रवाह नहीं, बल्कि आय, संपत्ति, पोषण, शिक्षा, निर्णय-क्षमता और समय-उपयोग जैसे संकेतकों को भी शामिल किया जाए।

10. निष्कर्ष

बिहार में विश्व बैंक समर्थित जीविका कार्यक्रम ने महिला सशक्तीकरण और स्वयं सहायता समूह आधारित ग्रामीण विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रभाव उत्पन्न किया है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि गरीब ग्रामीण महिलाओं का व्यापक संस्थागत संगठन है। 11.40 lakh स्वयं सहायता समूहों और 1.40 crore से अधिक परिवारों तक पहुँच यह बताती है कि जीविका बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला-केंद्रित विकास का प्रमुख माध्यम बन चुका है [5].

वित्तीय समावेशन के स्तर पर ₹59,156 crore का ऋण-प्रवाह, 10.49 lakh SHG बचत खाते और लाखों महिलाओं का बीमा कवरेज कार्यक्रम की गहराई को प्रमाणित करते हैं। सामाजिक स्तर पर महिलाओं की गतिशीलता, निर्णय-भागीदारी, सामुदायिक नेतृत्व और सामूहिक कार्रवाई में वृद्धि हुई है। फिर भी, कार्यक्रम की आगामी दिशा ऋण से आय, समूह से उद्यम, प्रशिक्षण से बाजार और वित्तीय पहुँच से आर्थिक स्वायत्तता की ओर होनी चाहिए। अतः जीविका को अब मात्र SHG विस्तार कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर महिला-नेतृत्व वाली ग्रामीण उद्यमिता और स्थानीय अर्थव्यवस्था पुनर्गठन के मॉडल के रूप में विकसित करना आवश्यक है।

© Copyright @ Authors

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

संदर्भ

1. बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी. "बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी: जीविका." पटना: बिहार सरकार।
2. विश्व बैंक. (2020). "बिहार राज्य में ग्रामीण विकास हेतु महिला समूहों की शक्ति का विस्तार." विश्व बैंक परिणाम-संक्षेप. वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।
3. विश्व बैंक माइक्रोडाटा पुस्तकालय. (2023). "बिहार में जीविका बहु-क्षेत्रीय अभिसरण पहल का प्रभाव मूल्यांकन सर्वेक्षण, 2018: पोषण सुधार हेतु महिला समूहों की सहभागिता." वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।
4. बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी. (2024). "वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट दस्तावेज, वित्तीय वर्ष 2024–25." पटना: ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार।
5. बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी. (2025). "जीविका 72वीं त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, जुलाई–सितम्बर 2025." पटना: बिहार सरकार।
6. दत्ता, यू. (2015). "भारत के बिहार राज्य में जीविका जैसी बड़े स्तर की स्वयं सहायता समूह परियोजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव." *वर्ल्ड डेवलपमेंट*, खंड 68, पृ. 1–18।
7. विश्व बैंक. (2016). "ग्रामीण बिहार की महिलाओं को सशक्त बनाने में जीविका की सफलता: पूर्वव्यापी सर्वेक्षण के परिणाम." दक्षिण एशिया कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रभाव टिप्पणी श्रृंखला. वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।
8. विश्व बैंक. (2019). "आजीविका एवं पोषण: महिला सशक्तीकरण और अभिसरण पहल—जीविका." वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।
9. बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी. (2024). "जीविका वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2023–24." पटना: बिहार सरकार।
10. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार. "दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: कार्यक्रम रूपरेखा एवं कार्यान्वयन प्रतिवेदन." नई दिल्ली: भारत सरकार।

© Copyright @ Authors